







परियोजना समाचार पत्रिका

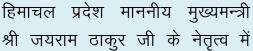
हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना परियोजना कार्यालय पॉटरस हिल, समरहिल, शिमला—5 हिमाचल प्रदेश दुरभाष: 0177-2830217, ई० मेल: cpdjica2018hpfd@gmail.com

अंक: 2

दिसम्बर 2019

माननीय वन मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का संदेश

सबसे पहले आपको परिवार सहित नव वर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं।



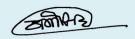


सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर तेज गति से बढ रहा है। पर्वतीय प्रदेश होने के नाते वानिकी एवं सम्बद्ध गतिविधियों की प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश वन विभाग को जापान सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना (JICA Funded) ''हिमाचल प्रदेश वन पारितंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना'' है। इन दिनों परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग द्वारा खूब परिश्रम किया जा रहा है जिसके लिए मैं विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों को बधाई देता हूँ। मुझे आपको जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि इस परियोजना में आपके क्षेत्र को भी शामिल किया गया है तथा परियोजना के प्रारम्भिक चरण का कार्य इन दिनों जोरों पर है। परियोजना के प्रारम्भिक चरण में बह्त से कार्याकलाप एवं व्यवस्थाएं अपेक्षित हैं, जिनमें आपके स्तर पर विभिन्न वार्डों / गाँवों का चयन, ग्राम वन विकास समितियों का गठन व माईक्रो प्लान तैयार करने के लिए चयनित गाँवों के लोगों के साथ बैठकें नर्सरियों का विकास, आने वाले वर्षों में पौधा रोपण के लिए तय मापदंडो के अनुसार वनों का चयन एवं उन वनों में जो पौधे रोपित होने हैं उनको नर्सरियों में उगाना इत्यादि शामिल है। अगले वित वर्ष से इस परियोजना का 'कार्यान्वयन चरण' आरम्भ हो जाएगा तथा परियोजना से सम्बंधित अन्य गतिविधियों जैसे विभिन्न माईक्रो प्लान बनाना, जड़ी बूटियों के सम्वर्धन, दोहन व विपणन जैसे कार्य भी किए जाएंगे।

परियोजना की गतिविधियों को अनन्तिम पंक्ति के लाभार्थी तक पहुँचाने के लिए परियोजना के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं तथा प्रशिक्षण एवं जागरूकता यात्राओं का आयोजन निरन्तर किया जा रहा है जो इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक जानकारियां जुटाने में महत्वपूर्ण है।

जिला कुल्लू में परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा सफल कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को कुल्लू के देव सदन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में विभाग के अधिकारी, फील्ड में कार्यरत कर्मचारी, जाईका परियोजना के अधिकारी/ कर्मचारी एवं ग्राम वन विकास समिति के पदाधिकारी अवश्य शामिल हों ताकि आने वाले समय में जाईका परियोजना की गतिविधियों की जानकारी व रुपरेखा, कार्यान्वयन की विधि व संचालन तथा भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की जा सके। शुभकामनाओं सहित,

आपका स्नेहकांक्षी,



(गोविंद सिंह ठाकुर)

मुख्य परियोजना निदेशक का संदेश

आपके हाथों में जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी (जाईका) द्वारा पोषित हि0 प्र0 वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबन्धन एवं आजीविका सुधार परियोजना के संवादपत्र का दूसरा संस्करण प्रदान करने के लिए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है।

विकास की वर्तमान सोच में सूक्ष्म नियोजन (माईक्रो प्लानिंग) ने एक निर्णायक पहल का स्वरूप ग्रहण कर लिया है, क्योंकि अछूते कार्यों को जानने व समझने की यह बहुत ही बारिक कार्य प्रणाली है। इसमें सामाजिक आर्थिक तथ्यों तक पहुँचने का प्रावधान है। इस आयोजन की प्रक्रिया जटिल है। इसलिए सूक्ष्म नियोजन का अनुपालन कार्य विभाग के वन मंडल अधिकारी /सहायक अरण्यपाल/वन परिक्षेत्राधिकारी /क्षेत्रिय तकनीकी ईकाई के सहयोग के बिना संभव नहीं हैं।

हि0 प्र0 वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबन्धन एवं आजीविका सुधार परियोजना के माध्यम से सूक्ष्म योजना प्रक्रिया पर वन प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अक्तूबर महीने में जाईका सूक्ष्म नियोजन परियोजना सलाहकार और परियोजना निदेशक (निगरानी व मुल्यांकन), कुल्लू की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यशाला में परियोजना लाईन स्टाफ जैसे वन रक्षक. परिक्षेत्राधिकारी, उप परिक्षेत्राधिकारी और फील्ड कॉर्डिनेटर स्टाफ को सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया और उनके सुझाव लिए गए। इस प्रशिक्षण शिवर का उद्देश्य परियोजना स्टाफ को वार्ड स्तर पर बनाई जाने वाली सूक्ष्म योजना के सम्बन्ध में जानकारी देना था। जिससे उन्हें वार्ड स्तर पर सूक्ष्म योजना व VFDS बनाने में आसानी रहे।

जैसे कि आप सभी भली—भांति परिचित है कि कुछ समय पहले जाईका प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी देने के लिए Pamphlets व परियोजना पुस्तिका जो कि परियोजना सलाहकारों की सहायता से बनाए गए थे, उन्हें सभी परियोजना से संबंधित जिलों, वन मण्डलों, वन परिक्षेत्रों, वन्य जीव मण्डलों और वन्य जीव परिक्षेत्रों तक पहुंचाया गया है। उम्मीद है कि आप सभी ने उसे पढ़ा होगा और हि0 प्र0 वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबन्धन एवं आजीविका सुधार परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी भी मिली होगी। ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे ताकि परियोजना की अधिक से अधिक जानकारी आप सभी तक पहुंच सके।

दीपावली से पहले मैंने एक अर्ध—शास्कीय पत्र भेजा था, जिसमें परियोजना से संबंधित जो अपेक्षाएं हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पत्र आप सब तक पहुँच गया होगा और वन मंडल अधिकारियों तथा वन परिक्षेत्राधिकारियों ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया होगा।

फील्ड में आप द्वारा सुझाये गए 76 वार्डों का अनुमोदन किया जा चुका है, जिनका ब्योरा जाईका प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पड़ने वाले मण्डलीय प्रबन्धन इकाई को भेज दिया गया है। वन मण्डल अधिकारियों से अनुरोध रहेगा कि VFDS गठन तथा पंजीकरण का कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न किया जाए। इसके साथ—साथ आपसे यह भी अनुरोध रहेगा जो intervention area चयनित किए गए है उसके दिशांक (Coordinates) इस कार्यालय को भेजने की कृपा करे ताकि हमारी GIS Cell उस पर अपना कार्य शुरु कर सकें।

इसके अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन इकाई और फील्ड के कुछ आधिकारियों को जागरूकता भ्रमण (Exposure Visit) के लिए उन राज्यों में भेजा गया है, जहां पर द्वितीय चरण में जाईका (JICA) परियोजना आरंभ हो चुकी है और वहां की सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया भी सफल हुई हैं। वहां से हमारे आधिकारिकों ने परियोजना से संबंधित कार्य सीखा है, जो आगे अपने-अपने क्षेत्रों की सूक्ष्म योजना बनाने में सहायक सिद्ध होगा। जागरूकता भ्रमण से प्राप्त Experience का भी सूक्ष्म नियोजन बनाने में सद्पयोग किया जायेगा। आने वाले समय में जहां-जहां सूक्ष्म नियोजन की गतिविधियां चली हुई है वहां के वन मंडल अधिकारी / सहायक अरण्यपाल / वन परिक्षेत्राधिकारी और वन रक्षकों को अलग–अलग राज्यों में जागरूकता भ्रमण के लिए भेजने का प्रावधान किया गया है। परियोजना कार्यान्वयन में आपकी सक्रियता और सहयोग, जागरूकता भ्रमण के लिए सहायक सिद्ध होगा।

हमनें परियोजना प्रबंधन इकाई कार्यालय में मुख्य वन संरक्षक (CCF) या CF अधिकारियों, वन मंडल अधिकारियों / सहायक अरण्यपालों, वन परिक्षेत्राधिकारियों और जाईका फील्ड कॉर्डिनेटरों के अलग—अलग WhatsApp Groups बनाए थे। लेकिन हमें FTU WhatsApp Group के अलावा उचित सकारात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं मिलीं। मेरी तरफ से आप सभी से यह विनम्र अनुरोध रहेगा कि कृपया सहयोग करें, ताकि हम सभी मीडिया के माध्यम से

परियोजना के अद्यतन के बारे में आसानी से संवाद कर सकें। आपसे एक प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि आप जो भी परियोजना से सम्बन्धित अच्छे कार्य कर रहे है, उन्हें लिख कर हमें भेजे ताकि अगले अंक में उन्हें शामिल करके बाकी पाठक भी लाभान्वित हो सके।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सब लोग परियोजना से संबंधित गतिविधियों को आपके क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध होगें। जो—जो कार्य जाईका परियोजना क्षेत्र के लिए चयनित किए जाएगें, उन्हें आप सभी समयबद्ध तरीके से संपूर्ण करेंगे।

अगले अंक में आपसे दोबारा संवाद करने का अवसर मिलेगा इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी कलम को यहाँ विराम देता हूँ।

> नागेश कुमार गुलेरिया, भा0व0से0 मुख्य परियोजना निदेशक, जाईका पोर्ट्स् हिल, शिमला–05

परियोजना मुख्यालय का उद्घाटन



4 अक्टूबर, 2019 को, माननीय वन, परिवहन, युवा सेवा और खेल मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर और श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री, श्री राम सुभाग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सिवव (वन), श्री अजय कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), हिमाचल प्रदेश वन विभाग, श्री नागेश कुमार गुलेरिया, मुख्य परियोजना निदेशक, हिमाचल प्रदेश वन विभाग के अन्य विरष्ठ अधिकारी, स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि और परियोजना के कर्मचारियों की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया।



इस अवसर पर, श्री गोविंद सिंह ठाकुर माननीय वन मंत्री, हिमाचल प्रदेश ने सभी उपस्थिति लोगों को परियोजना के लक्ष्य से अवगत कराया कि इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश के छह जिलों- बिलासपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, और लाहौल तथा स्पीति में पर्यावरण और सतत सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करते हुए वन पारिस्थितिकी प्रणालियों का प्रबंधन और संवर्द्धन करना है। इसका उद्देश्य जल संसाधन संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकने और स्थानीय निवासियों के स्थायी वैकल्पिक आजीविका को बढ़ाने के साथ-साथ जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार के लिए योगदान करना है। इसके अलावा माननीय मंत्री ने परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु शुभकानाएं दी

परियोजना अधिकारियों का जागरूकता भ्रमण



अधिकारियों का प्रथम बैच



अधिकारियों का द्वितीय बैच

परियोजना अधिकारियों के दो बैचों ने त्रिपुरा SCATFORM प्रोजेक्ट का दौरा परियोजना गतिविधियों को जानने के लिए किया। पहले बैच में श्री नागेश कुमार गुलेरिया, मुख्य परियोजना निदेशक, JICA (PIHPFEM&L) पॉटरस हिल, शिमला, श्रीमती उपासना पटियाल, सीसीएफ, मंडी सर्कल, शर्मा, परियोजना निदेशक मीरा (PIHPFEM&L), कुल्लू , श्री मनोज कुमार, ACF कुल्लू, डॉ। अमन शर्मा, कार्यक्रम प्रबंधक (वानिकी और जैव विविधता) और दूसरे बैच में श्री रमन शर्मा, परियोजना निदेशक, प्रशासन JICA, पॉटरस हिल, शिमला, श्री चंदूलाल बाबूलाल तसीलदार, डीएफओ रोहड़, श्री चंदर भूषण, डीएफओ आनी, श्री एंजल चौहान, डीएफेंओ पार्वती, सुश्री नेहा चक्रवर्ती, कार्यक्रम प्रबंध (विपणन और ग्रामीण वित्त) और श्री गिरीश ठाकुर SMS (आजीविका, मार्केटिंग एंड रूरल फाइनेंसिंग) ने त्रिपुरा SCATFORM प्रोजेक्ट (त्रिपुरा JICA-II परियोजना) का दौरा क्रमांश 06-10 और 21-23 नवंबर, 2019 को परियोजना गतिविधियों को जानने के लिए किया। प्रतिभागियों ने माइक्रोप्लानिंग, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन और आजीविका गतिविधियों के बारे में सीखा।

जागरूकता भ्रमण का उद्देश्य:

- संगठनात्मक संरचना, प्रबंधन और कार्यान्वयन में VFDS सदस्यों की भागीदारी को समझना।
- माइक्रो प्लान तैयार करने के अनुभव को सांझा करना।
- त्रिपुरा JICA चरण-I परियोजना में JFMC की आय सृजन / आजीविका गतिविधियों में भूमिका के अनुभव को सांझा करना।
- त्रिपुरा JICA परियोजना के तहत विकसित मॉडल नर्सरी का दौरा करना ।

त्रिपुरा JICA चरण-I परियोजना:-

परियोजना का नाम: त्रिपुरा वन पर्यावरण सुधार और गरीबी उन्मूलन परियोजना

परियोजना अवधि: 2007-2017

बजट: 365 करोड रुपये

परियोजना क्षेत्र: 7 जिलों और 40 फ़ॉरेस्ट रेंज

JFMC बनाई: 463

लाभार्थी परिवारों की संख्या: 35,593

पौधारोपण: 79.538 हेक्टेयर

SHG बनाई: 1549

अन्य कार्य: वन नर्सरी, मत्स्य, कृषि-वानिकी मॉडल,

इकोटूरिज्म साइट, NTFP सेंटर ऑफ

एक्सीलेंस (NCE)।

त्रिपुरा JICA चरण-II परियोजना:-

सतत कैचमेंट फ़ॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना नाम: (SCATFORM) परियोजना

परियोजना लॉन्च: 16 जनवरी 2019

परियोजना का उद्देश्य: वन गुणवत्ता, मृदा और नमी संरक्षण, आजीविका विकास में सुधार करना है।

गतिविधियाँ:नर्सरी, वृक्षारोपण मॉडल, मृदा और नमी संरक्षण, NTFP- आधारित, कृषि-वानिकी आधारित, पशु और मछली पालन, जैविक खेती, इकोटूरिज्म विकास, क्लस्टर विकास, 3 स्तर -संग्रह और प्राथमिक प्रसंस्करण है।

प्रतिभागियों को PrCCF त्रिपुरा, विभिन्न बैंकरों और JICA प्रोजेक्ट त्रिपुरा के कर्मचारियों के साथ JICA प्रोजेक्ट-II के बारे में बातचीत करने का अवसर मिला। यह योजना समुदायों को बैंकों से जोड़कर पूर्व परियोजना की आजीविका और मुल्य संवर्धन गतिविधियों को बढावा देने के लिए है। प्रथम चरण-। में बनाई गई माइक्रोप्लेनिंग प्रक्रिया की जानकारी के लिए फील्ड स्टाफ के साथ बातचीत भी हुई। साथ ही समुदाय के सदस्यों, हितधारकों, समूह के सदस्यों और विभिन्न JFMC के सदस्यों के साथ बातचीत की और उनके द्वारा किये गए कार्य की सफलताओं और कठिनाइयों के बारे में सीखा तथा परियोजना द्वारा किए गए बांस वृक्षारोपण क्षेत्र का दौरा किया।

उदयपुर सब-डिवीजन गोमती जिला की परटिया सेंट्ल नर्सरी का भी दौरा किया गया यहाँ नर्सरी को मॉडल नर्सरी के रूप में विकसित किया गया है, और पॉली बैग के विकल्प के रूप में नर्सरी में कोको पीट के उपयोग के बारे अपनाई जा रही तकनीकी जानकारी हासिल की।

परियोजना के तहत विकसित सामुदायिक अध्ययन केंद्र की यात्रा के दौरान, गोमती में हितधारक क्लस्टर समूह के सदस्यों, विभिन्न JFMC के सदस्यों और मिट्टी के बर्तनों की गतिविधियों में शामिल समूह के साथ बातचीत की गई। जिसमें लोगों ने बताया कि परियोजना समाप्ति के बाद उन्हें विपणन की समस्या आ रही है।

- त्रिपुरा की एक्सपोज़र यात्रा से स्टाफ माइक्रोप्लानिंग प्रक्रिया से परिचित हुए और परियोजना क्षेत्र में माइक्रो प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है।
- हिमाचल प्रदेश वन विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ अपने अनुभव सांझा किया जा रहा है।
- त्रिपुरा की मॉडल नर्सरी से सीखे गुरों को हिमाचल प्रदेश में भी नर्सरी प्रबंधन में शामिल किया जायेगा।

प्रशिक्षण एवं कार्यशालाऐं

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना की दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन वन प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर में किया गया इस प्रशिक्षण में परियोजना के अन्तर्गत चयनित प्रथम चरण की ग्रामीण वन प्रबंधन समितियों के क्षेत्रों के वन रक्षकों, उप वन राजिकों तथा परियोजना में अनुबन्ध पर लिये गये कर्मचारी, विषय विशेषज्ञों, वन तकनीकी इकाई समन्वयकों इत्यादि को ग्रामीण वन विकास



समिति स्तर पर सूक्षम योजना बनाने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में 54 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिसमें 33 पुरूष तथा 21 महिला प्रतिभागी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण श्री गिरीश भारद्वाज Consultant (PMC) तथा परियोजना निदेशक श्रीमती मीरा शर्मा द्वारा दिया गया। इस प्रशिक्षण में सूक्षम योजना बनाने, ग्रामीणों को जागरूक करने की विधि व प्रक्रिया के बारे में बताया गया तथा सूक्षम योजना के लिए जानकारी एकत्रित करने हेतु उपयोग किये जाने वाले प्रपत्रों को भी सांझा किया

गया तथा उनसे प्रतिपुष्टि ली गई ताकि प्रपत्रों को सरल किया जा सके।



शुभारम्भ अतिरिक्त प्रधान का अरण्यपाल, अनुसंधान और प्रशिक्षण श्री एच० एस० डोगरा द्वारा किया गया तथा प्रशिक्षण का समापन समारोह श्री नागेश गुलेरिया द्वारा किया गया। श्री ग्लेरिया जी ने बताया कि इस प्रशिक्षण के बाद परियोजना वार्ड स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अग्रसर है तथा पायलट स्तर पर सूक्षम योजना बनाने की प्रकिया 22.10. 2019 से दो वन मण्डलों, कुल्लू वन मण्डल तथा रोहडू वन मण्डल में शुरू की जा रही है जिसमें विषय विशेषज्ञों, वन तकनीकी समन्वयकों. वन रक्षकों तथा उप वन रक्षकों को शामिल किया जा रहा है। दिसम्बर माह के आखिर तक इन दो पायलट स्तर पर सूक्षम योजना को पूर्ण किया जाऐगा तथा इसके आधार पर चयनित अन्य 75 ग्रामीण वन विकास समिति क्षेत्रों में सूक्षम योजना बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

ग्रामीणों के साथ सूक्षम योजना बनाते परियोजना कर्मचारी

कुल्लू वन मंडल की बस्तोरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत दो सूक्षम योजनाएं बनाई गयी हैं। एक सरली वार्ड में तथा दूसरी नथान -१, नथान-२ तथा बस्तोरी वार्ड के लिए इक्क्ठी सूक्षम योजना बनाई गयी।



नथान -१ में परियोजना कर्मचारी ग्रामीणों के साथ PRA करते हुए

इस का प्रशिक्षण परियोजना निदेशक श्रीमती मीरा शर्मा द्वारा दिया गया ।



आमसभा, सरली, ग्रामीण वन विकास समिति

रोहड़ू वन मंडल के अधीन छाजपुर वार्ड में सूक्षम योजना श्री गिरीश भारद्वाज, टीम लीडर, समुदाय आधारित वन प्रबंधन, (पीएमसी) के दिशा निर्देश में बनाई गई है।



छाजपुर, रोहडू वन मंडल में ग्रामीणों के साथ वार्तालाप करते हुए परियोजना कर्मचारी

कुल्लू, मंडी, सुंदरनगर, सुकेत, रोहडू, ठियोग, बिलासपुर और शिमला वन मंडल में भी सूक्ष्म योजनाओं और VFDS गठन के कार्य के लिए ग्रामीण सहभागी मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया गया है।



बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत PRA करते हुए परियोजना स्टाफ

सूक्ष्म योजना बनाने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

- 1. तकनीकी कर्मचारियों द्वारा संभावित क्षेत्र की पहचान (वन कर्मचारी)।
- 2. ग्राम पंचायत की जागरूकता बैठक (द्वितीयक आंकडों का संग्रह करना जैसे कि वार्डो की संख्या, घरों की संख्या, जाति, आवास, लोगों के वन अधिकार आदि)
- 3. वार्ड स्तर की अनौपचारिक बैठक यदि वे रूचि रखते हैं।
- 4. परियोजना गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायत की सहमति।
- 5. वार्ड स्तर की अनौपचारिक बैठक— बालन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकडी़, घास, महिला की स्थिति, जाति प्रथा व व्यवस्था, जल स्त्रोत पर अनौपचारिक आंकडें एकत्रित करना।
- 6. समरूचि समूहों तथा सिक्य सदस्यों की महिलाओं व पुरूषों की पहचान करना।
- 7. वार्ड स्तर की अनौपचारिक बैठकों का आयोजन जिसमें परियोजना उदेद्श्य, लक्ष्य, गतिविधियों और कार्यन्वयन का विवरण देना।
- उपभोक्ता समूहों / क्ति समूहों / महिला मण्डल व युवक मण्डलों की पहचान करना।
- 9. वन परिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन परियोजना की तैयारी के लिए आंकडें एकत्रित करना तकनीकी कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र का दौरा करके जी0पी0एस0 निर्देशांक द्वारा स्थान की पहचान करना।

- 10. गुगल अर्थ पर वन परिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन परियोजना (FEMP) के आंकडों को सत्यापित करना, तकनीकी कर्मचारी / जी0आई0एस0 सेल द्वारा आधार मानचित्र तैयार करना।
- 11. सिक्वय सदस्यों तथा ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को जी0आई०एस० सेल द्वारा बनाये गये मानचित्र का क्षेत्रों में जाकर सत्यापन करना, सम्भावित क्षेत्रों की सीमाओं तथा स्थिति की जी०पी०एस० निर्देशांक लेना।
- 12. लोगों के साथ बैठक करना तथा वन विकास प्रबंधन समिति तथा वन विभाग द्वारा जिन क्षेत्रों / रक्वों में कार्य किया जाना है की पहचान करना है।
- 13. क्षेत्रीय तकनीकी इकाई समन्वयक (FTU Coordinator) द्वारा आंकडों का संग्रह, विश्लेषण और संकलन करना।
- 14. क्षेत्रीय तकनीकी इकाई समन्वयक (FTU Coordinator) द्वारा उपयोगकर्ता समूहों का गठन करना।
- 15. तकनीकी कर्मचारियों द्वारा रक्वों का विवरण लिखना (सहायक अरण्यपाल, वन राजिक, उप वन राजिक, वन रक्षक)।
- 16. परियोजना द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का विवरण तकनीकी योजना वन पारिस्थितिकी प्रबंधन योजना (FEMP) में शामिल करना

- 17. सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार परियोजना की गतिविधियों की पहचान करना तथा योजना तैयार करना (वार्ड फैसिलिटेटर, वन तकनीकी इकाई समन्वयक (FTU Coordinator)।
- 18. आम सभा की बैठक का आयोजन तथा वन विकास समीति का आयोजन, कार्यकारी समिति का गठन करना तथा परियोजना के प्रारूप के विषय में चर्चा करना।
- 19. चर्चा के दौरान ग्रामीणों द्वारा दिये गये सुझावों को योजना में शामिल करना।
- 20. सूक्ष्म योजना को अन्तिम रूप देने के लिए ग्राम सभा का आयोजन करना।

- 21. वार्ड सभा द्वारा सूक्ष्म योजना का अनुमोदन।
- 22. वन तकनीकी इकाई समन्वयक (FTU) द्वारा ग्रांमीण वन विकास समीति का पंजीकरण करवाना।
- 23. सूक्ष्म योजना को वन तकनीकी इकाई (FTU) द्वारा मण्डलीय प्रबंधन इकाई (DMU) को अनुमोदन हेतु भेजना।
- 24. प्रारम्भिक 75 सूक्ष्म योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) को भेजना।
- 25. एक वर्ष बाद सूक्ष्म योजना प्रक्रिया को अनुश्रवण व मूल्यांकन इकाई (M&E) की प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।



सेंट्रल नर्सरी कुल्लू वन वृत मौहल

प्रकाशन: - अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजिविका सुधार परियोजना कुल्लू विस्तृत जानकारी के लिए संर्म्पक करें: -

- 1. मुख्य परियोजना निदेशक, जाईका वानिकी परियोजना, पॉटरस हिल, समरहिल, शिमला–5 हिमाचल प्रदेश दुरभाष: 0177-2830217, ई० मेल: cpdjica2018hpfd@gmail.com
- 2. परियोजना निदेशक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, जाइका वानिकी परियोजना, कुल्लू। दूरभाष:1902 -226636, ई0 मेल: -pdjicakullu@gmail.com
- 3. उप परियोजना निदेशक, सामूदायिक एवं संस्था क्षमता उत्थान इकाई, जाईका वानिकी परियोजना, रामपुर। दूरभाष: 01782-234689, ई0 मेल: -dpdrmp2018@gmail.com









PROJECT NEWS LETTER

Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management & Livelihoods

Project office Potters' Hill, Summer Hill, Shimla -5 Himachal Pradesh Telephone: 0177-2830217, E-mail: cpdjica2018hpfd@gmail.com

ISSUE:2 December 2019

Chief Project Director Message

The second edition of the newsletter of Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods funded by Japan International Cooperation Agency is in your hands.

Micro-Planning plays an important role in understanding even the smallest works and the nitty gritty involved in its implementation. It has provisions to know about the socio-economic conditions of the areas where micro-planning processes are being implemented. To accomplish the arduous task of preparing micro-plans, the officials of the Forest Department especially DFOs, ACFs, ROs, FTUs play a vital role. Without their efforts the completion of these plans wouldn't be possible.

A two day workshop at the Forest Training Institute, Sunder Nagar on Micro-Planning process through PIHPFEM&L was organized in the month of October under the Chairmanship of JICA Micro-Planning Project Consultant and Project Director (M&E), Kullu. In this workshop, the front line staff viz Range Officers, Deputy Rangers, Forest Guards, SMSs and FTUs were trained on the Micro-Planning process. Micro-Planning templates were discussed while also incorporating their valuable suggestions. The purpose of this training was to guide field staff to follow similar steps in making micro plan at ward level. I appreciate, Ms. Meera Sharma, Project Director (M&D), Kullu and Mr. Girish Bhardwaj Project Consultant for their contribution in making this training a success. The Sincere efforts of Ms. Richa Mehta, Programme Manager and Ms. Reena, SMS were also highly appreciable.

As you are all well aware that for provide information related to JICA Project, the Pamphlets and Project Manuals were created with the help of Project Consultants. They were distributed to all the Project related Districts/Circles, Forest Divisions, Forest Ranges, Wildlife Divisions and Wildlife Ranges. Hopefully, you all have read it and also got detailed information about Project for Improvement of

Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods. Such efforts will continue even further so that maximum and latest information about the Project could reach at the lowest level of the hierarchy.

Before Diwali, I'd also written a DO letter, discussing about our expectations from the project. I hope you all have received this letter and the DFOs and ROs have started working in the field. 76 wards falling under different DMUs (Divisional Management Units) have also been approved following their recommendations. I insist all the DFOs to constitute VFDSs and start registration process at the earliest. Along with that I request that the GPS coordinates of the potential intervention areas may also be sent to PMU so that the GIS cell starts its work accordingly.

A few officers & officials of the Project Management Unit also visited JICA project in other states, where the 2nd phase of JICA project has started and the micro- planning process has been a success in its 1st phase. Learning from the experiences and challenges faced in those areas, officers of our project would be able to form better micro-plans and implement the project activities efficiently in their respective jurisdictions. We plan to carry out such exposure visits for DFOs/ACFs/ROs and FGs of project area in the near future, to create awareness and increase their exposure on the topic which would help in better implementation of the project activities.

PMU has also created WhatsApp groups for CCFs, CFs, DFOs, ACFs, ROs and FTOs. The only group actively participating is the FTU group, while others are still not responding. I insist you all to kindly contribute your ideas and suggestions on these platforms to increase cross flow of knowledge. I also request you to promote quality works related to the project and forward it to us. We would ensure that they are included in the forthcoming editions of News letter so that rest of the readers could also be benefitted. I hope that you will remain committed for the project

activities pertaining to your area and complete these in a time bound manner.

With a hope to interact with you all again through our next edition, I would like to take your leave now.

With best regards Thank you

> Nagesh Kumar Guleria, IFS Chief Project Director, JICA Potters Hill, Shimla-05

Inauguration of Project Headquarter



On 4th October, 2019, Hon'ble Forest, Transport and Youth Services & Sports Minister Shri.Govind Singh Thakur together with Shri. Suresh Bhardwaj Hon'ble Education Minister, accompanied by Shri Ram Subhag Singh, Additional Chief Secretary (Forests), Shri Ajay Kumar, Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Himachal Pradesh Forest Department, Shri Nagesh Kumar Guleria (IFS), Chief Project Director, Senior officials of HPFD, representatives from local communities, and the project staff inaugurated the Project Headquarter of JICA-supported Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods.

On this occasion, Shri Govind Singh Thakur, Hon'ble Forest Minister, Himachal Pradesh apprised everyone that the project's goal is to manage and enhance forest area ecosystems while contributing to



environmental and sustainable socio-economic development in six district - Bilaspur, Shimla, Mandi, Kullu, Kinnaur, and Lahaul & Spiti. It aims to contribute to biodiversity conservation improvement of ecosystem services with specific focus on water resource conservation, prevention of soil erosion, and necessary support to establish sustainable alternative livelihoods of local residents. Also Hon'ble Minister blessed the project straff with great success of the project.

Inauguration of this Headquarter is a stepping stone towards integrating and establishing one strong identity of the Project, which will promote a culture of collaboration, creativity, and concerted efforts to achieve envisaged objectives of sustainable environmental and social development in Himachal Pradesh.

Training & Workshops



Two days training workshop was organized for the process of micro planning for the 1st batch VFSDs at FTI Sunder Nagar for the FTU Coordinator, SMS and Front Line Staff of Bilaspur, Shimla, Mandi and Kullu districts of Himachal Pradesh. Total 54 participants showed



presence in the traning workshop. Smt. Meera Sharma, CF-cum- Project Director, Kullu and Mr. Girish Bhardwaj, Team Leader, Community based Forest Management PMC, explained to trainee in detail about the micro plan templet and micro planning process. On

the closing day of training workshop Chief Project Director, Mr. Nagesh Guleria attended the workshop & announced that in Kullu and Rohru forest Divisions Micro planning would be started on pilot basis from 22nd October 2019 to 8th November 2019, under the leardesrship of Smt. Meera Sharma in Kullu Forest Division and Mr. Girish Bhardwaj in Rohru Forest Division. Chief Project Director also told that on the basis of learning from these pilots Micro Plans rest of the microplans of first batch will be completed within this financial year.

Events/meetings/workshops/trainings held w.e.f. October 2019 to December, 2019

- 8th Executive committee Meeting of project held on 5 November 2019.
- Orientation Workshop held for staff at Mandi on 1 October, 2019.
- Practical training to Field staff in PRA exercises and Microplanning process held w.e.f 22 October, to 8 November, 2019.

Project Officer's Exposure Visit



Frist Batch of Offficers

Two batches consisting of officer's in first batch included Mr. Nagesh Kumar Guleria (CCF) Chief Project Director, JICA assisted PIHPFEM&L, Potters' Hill, Shimla, Mrs. Upasna Patial, CCF, Mandi Circle, Mrs. Meera Sharma (CF) Project Director, JICA assisted PIHPFEM&L, Kullu. Mr. Manoj Kumar, ACF, Kullu, Dr. Aman Sharma, Programme Manager (Forestry & Biodiversity) and in second batch Mr. Raman Sharma, Project Director Admin. Shimla, JICA, Mr Chandulal Babalal Tashildar, DFO, Rohru, Mr Chander Bhushan, DFO, Anni, Mr. Mr Angel Chauhan, DFO, Parvati, Ms Neha Chakravarty, Programme Manager (Marketing and Rural Financing) and Mr Girish Thakur SMS (Livelihoods, Marketing and Rural Financing) visited Tripura SCATFORM Project (Tripura JICA phase II Project) on 06-10 November, & from 21-23Nov, 2019, to learn JICA project activities being run in Tripura. Participants learnt about Microplanning, M&E, and Livelihood activities.

Objective of the Exposure Visit was:

- To understand the organizational structure, management practices and involvement of VFDS members in planning and implementation
- Two way experience sharing on preparation of Micro Plans
- Exposure visit to JFMCs and various income generation/Livelihood activities taken up in Tripura JICA phase I Project



Second Batch of Officers

• visit the model nurseries developed under the Tripura JICA Project

Tripura JICA Phase I Project:

Project Name: Tripura Forest Environmental Improvement and Poverty Alleviation

Project.

Project Period: 2007-2017 Total budget: Rs. 365 crores.

Project Area: 40 Forest Ranges of 7 Districts

Total JFMCs Formed: 463 JFMCs

Benefited families: 35,593 **Plantation area:** 79,538 ha **Total SHGs formed:** 1549.

Other works: Forest nurseries, fishery, agro-forestry models, ecotourism sites, NTFP Centre

of Excellence (NCE)

Tripura JICA Phase II Project:

Project Name: Sustainable Catchment Forest Management (SCATFORM)

Launched: 16 January 2019

Objective of the project: To improve forest quality, Soil & Moisture Conservation & Livelihood development

Project activities: Nurseries, Plantation Models, Soil & Moisture Conservation, NTFP-based, Agro-forestry based, Livestock & fish farming, Organic farming, Ecotourism

development, Cluster Development - 3 tiers - Collection & primary processing.

Paticipants got an opportunity to interact with PrCCF Tripura and different bankers, JICA Project Tripura staff on finalization of a scheme to be implemedted in IInd phase of JICA Project. This was a scheme for promotion of value addition of livelihood activities of ealier project by linking the communities with bankers for loan schemes. Interaction with field staff was also held to see the Microplanning process followed in Tripura JICA phase I. Also interacted with community members, the stakeholders, cluster group members and members of different JFMCs and learnt about their successes and difficulties faced by them. The participants also visited bamboo plantation done by the Tripura JICA project through JFMCs.

Paratia Central Nursery of Udaipur Sub-division of Distt. Gomti in Tripura is developed as model nursery under JICA project. They learnt about use of coco peat in nursery as an alternate to the poly bag and got acquainted with the technique.

During visit to the Community Learning Centre developed under the project in the Udaipur Sub-division of Distt.Gomti interacted with the stakeholder, cluster group members and members of different JFMCs and group involved in pottery activities. They intimated that after closure of project they are finding problem in marketing.

- Exposure visit to Tripura would help our staff in Microplanning Process and incorporate the relevant lessons learnt regarding the Micro Plan Process while preparing the Micro Plans under PIHPFEM&L.
- Share experiences with other staff in PIHPFEM&L Himachal Pradesh and forest Department.
- Incorporate the relevant lessons learnt from Model nursery of Tripura in nurseries of our JICA assisted project.

Microplanning in Project Area

Micro planning of Bastori Gram Panchayat of Kullu Forest Division and Chhajpur ward of Anti Gram Panchayat of Rohru Forest Division was started from 22nd October 2019 to 8th November 2019 on pilot basis in the leardesrship of Smt. Meera Sharma, (CF) Project Director in Kullu Forest Division and Mr. Girish Bhardwaj, Team Leader, Community Based Forest Management, PMC in Rohru Forest Division. The



PRA execise in Nathan-1 in Kullu Forest Division



Discussion with villagers of Chhajpur, Rohru Forest Division

Micro Plans of Sarli, Bastori and Chhajpur wards nearly completed and initial steps for the formation of VFDSs started in the respective wards. Participatory Rural Appraisal exercise have started for the prepation of micro plans and constitution of VFDS in Kullu, Mandi, Sundernagar, Suket, Rohru, Theog, Bilaspur and Shimla Forest Divisions also.



General House of Sarli VFDS, Kullu Forest Division



PRA execise in Bilaspur Forest Division

Steps of Microplanning Process

Following steps are being taken for the microplanning process:-

- Potential area identification by technical staff (Forest staff)
- Awareness Meeting GP(secondary data collection such as no of wards, no of HHs, caste, hamlets, people forest rights etc.
- Ward level informal meetings, if found interested
- GP consent for project activities
- Ward level informal meetings and informal data collection on fire wood collection, grass collection, women status, caste system, water source etc.
- Identification of interest group, active memberswomen & men
- Ward level formal meetings (Project objectives, goal, activities and implementation details.)
- Identification of User Groups/interest groups/Mahila Mandal/Yuvak Mandal
- Data collection for FEMP preparation, technical staff field visit to collect GPS co-ordinates of identified sites, Social Staff to collect social data.
- Verifying on Google earth, preparation of base map by Tech. staff/GIS Cell
- Field truthing with map, and marking the exact locations and physical boundaries of available potential area on the base map. Taking GPS Locations of each plot. Active members/ Gram Panchayat representative to be involved in this process.

- Meeting with people using the identified area or plot for segregation of PFM & Forest Department mode activities
- Compilation of data collected and analysis by FTU Co-ordinators.
- User group formation by FTU Co-ordinators.
- Plot descriptions by technical staff(ACF, RO, Dy Ranger, Forest Guard)
- Project interventions prescriptions in tech plan (Tech staff)
- CD&LIP activities identification and plan preparation social staff (Ward facilitator, FTU coordinator)
- GH meeting to constitute VFDS, GH, EC & to discuss draft plan
- Including of suggestions of villagers in micro plan
- Next GH Meeting to finalize the plans, which includes convergence activities too.
- Approval by GH of Ward Sabha
- VFDS Registration by FTU (Range Officers)
- Micro Plan sent to FTU, then to DMU by FTU
- Initial 75 MPs to be sent to PMU for Financial approval
- After one year if needed, Micro Planning process can be revised based on M&E feedback.

Published by: - M&E Cell PIHPFEM&L (HP JICA Forestry Project) Kullu For further details please Contact: -

- 1. Chief Project Director PIHPFEM&L (HP JICA Forestry Project), Potters' Hill, Summer Hill Shimla-5, Ph.No. 0177-2830217 (O) E-mail: cpdjica2018hpfd@gmail.com
- 2. Project Director, Monitoring & Evaluation, PIHPFEM&L (JICA Forestry Project, Kullu) Ph. No. 1902 -226636, e-mail-pdjicakullu@gmail.com
- 3. Deputy Project Director, Community & Institutional Capacity Building, PIHPFEM&L (JICA Forestry Project, Rampur); Ph. No. 01782-234689, e-mail-drmp2018@gmail.com